



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 25, 2011/फाल्गुन 6, 1932

No. 48]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25, 2011/PHALGUNA 6, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2011

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विस्कोस फिलामेंट यार्न के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

सं. 15/23/2010-डीजीएडी.—यतः समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन, संग्रहण एवं क्षति-निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे एतदपश्चात् पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए चीन जन.गण. (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विस्कोस फिलामेंट यार्न (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क सबसे पहले दिनांक 4 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना सं. 14/23/2004-डीजीएडी द्वारा लगाया गया था; जिसके पश्चात दिनांक 24 मई, 2006 की सीमा-शुल्क अधिसूचना सं. 45/2006 द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। और यतः दिनांक 22 मई, 2009 के अंतिम जांच परिणाम सं. 15/8/2007-डीजीएडी द्वारा मध्यावधि समीक्षा जांच द्वारा इस जांच परिणाम में संशोधन किया गया था; जिसके पश्चात् दिनांक 13 जुलाई, 2009 की सीमा-शुल्क अधिसूचना सं. 81/2009 द्वारा पाटनरोधी शुल्क में संशोधन किया गया था।

2. विचाराधीन उत्पाद

मूल जांच में शामिल जिस उत्पाद पर विचार किया गया था वह चीन जन.गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित 150 डेनियर (और उसके $\pm 4\%$ तक अनुमेय अंतर वाला) विस्कोस रेयॉन फिलामेंट यार्न, जिसमें 67 डेसीटेक्स से कम मोनो फिलामेंट यार्न जिसे विस्कोस फिलामेंट यार्न अथवा वीएफवाई के नाम से भी जाना जाता है शामिल है, जिसमें 100% विस्कोस यार्न से निर्मित सभी यार्न आते हैं जैसे रेजिट यार्न, फ्लैट यार्न, माइक्रोफिलामेंट माइक्रो यार्न, ट्रिवस्टेड यार्न (एम्ब्राइडर्ड यार्न को छोड़कर), जब तक इस पैराग्राफ में विशिष्ट रूप से अपवर्जित न हो, वीएफवाई के डबल/मल्टिपल प्लाई यार्न आदि (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध वस्तुएं भी कहा गया है) था। इस समीक्षा के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में था।

संबद्ध वरतुं रीमाशुल्क उपशीर्ष 54033100, 54033200, 54033300, 54034110, 54034120, 54034130, 54034140, 54034150, 54034160, 54034170, 54034180 और 54034190 के अंतर्गत वगीकृत हैं; हालांकि यह सूचित किया गया है कि उनका आयात (इस विषय पर की गई विगत जांच में) अन्य अध्यायों (जैसे अध्याय 55) के अन्य शीर्षों के अंतर्गत भी किया गया है। इस प्रकार सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और इस जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

3. जांच शुरूआत

इण्डियन मॅटल एण्ड फैरो एलॉयज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2006 की रिट याचिका (सिविल) सं. 16893 के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसरण में प्राधिकारी संबद्ध वरतुओं पर लागू शुल्क के अधिरोपण को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क को समाप्त करने की परिणति पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति में होने की संभावना है, एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं।

4. शामिल देश/राज्य क्षेत्र

इस जांच में शामिल देश चीन जन.गण. है।

5. जांच अवधि

वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई) दिनांक 1 अक्टूबर, 2009 से 30 सितम्बर, 2010 (12 माह) है। तथापि क्षति विश्लेषण में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 और जांच अवधि शामिल होगी। पाटन और क्षति की संगावना के निर्धारण के लिए जांच अवधि के परवर्ती आंकड़ों की जांच की जा सकती है।

6. प्रक्रिया

दिनांक 4 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना सं. 14/23/2004-डीजीएडी द्वारा जारी अंतिम जांच परिणाम, जिन्हें मध्यावधि समीक्षा जांच में दिनांक 22 मई, 2009 के अंतिम जांच परिणाम द्वारा संशोधित किया गया था; जिसके उपरांत क्रमशः दिनांक 24 मई, 2006 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 45/2006 और दिनांक 13 जुलाई, 2009 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 81/2009 द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था, की समीक्षा का निर्णय लेने के उपरांत प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा निर्यातित संबद्ध वरतुओं के आयातों पर लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की परिणति "पाटन" एवं "क्षति" के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति में होने की संभावना है, उक्त अधिनियम और पाटरोधी नियमावली के अनुसरण में एतद्वारा जांच की शुरूआत करते हैं। इस समीक्षा में दिनांक 4 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना सं. 14/23/2004-डीजीएडी (मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम), जिन्हें मध्यवधि समीक्षा जांच में दिनांक 22 मई, 2009 के अंतिम जांच परिणाम सं. 15/8/2007-डीजीएडी द्वारा संशोधित किया गया था, के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा।

7. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत के ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं को निर्धारित स्वरूप एवं ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने तथा प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
कमरा सं. 240, उद्योग भवन
नई दिल्ली - 110011

अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संगत निवेदन कर सकता है।

8. समय सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु किया गया कोई भी अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर पहुँच जाना चाहिए। यदि निर्धारित समयावधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

संबद्ध वर्तुओं के घरेलू उत्पादकों को एक प्रश्नावली जारी की जा रही है जिसका उत्तर पाटनरोधी उपायों के अधिरोपण को जारी रखने की आवश्यकता का प्रमाण देते हुए 40 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे प्रस्तुत मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) के बारे में इस जांच की शुरूआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचित करें। ऐसे भी हितबद्ध पक्षकारों से, जो इस प्रकार सूचित करते हैं, पाटनरोधी उपायों को जारी रखने अथवा नहीं रखने की आवश्यकता के बारे में उन्हें जारी किए गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर घरेलू उत्पादकों के उत्तर (उत्तरों) पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाएगा।

9. गोपनीय आधार पर उत्तर प्रस्तुत करना

प्रश्नावली के उत्तर/निवेदन के किसी भाग पर गोपनीयता का दावा किए जाने के मामले में इसे दो अलग-अलग भागों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए; (क) गोपनीयता के रूप में चिन्हित (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि) और (ख) दूसरा भाग अगोपनीय के रूप में चिन्हित (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि) उपलब्ध कराई गई समस्त सूचना में प्रत्येक पृष्ठ पर ऊपर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" लिखा जाना चाहिए।

बिना विहन के उपलब्ध कराई गई सूचना अगोपनीय समझी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी किसी भी अगोपनीय सूचना के निरीक्षण की अनुमति प्रदान करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

जिस सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है उस सूचना के आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराई गई सूचना के साथ कारणों का ब्यौरा प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती है एवं/अथवा ऐसी सूचना का संक्षेप क्यों संभव नहीं है।

अगोपनीय घाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए और जिस सूचना के बारे में गोपनीयता का दावा किया गया हो उसे अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा मिटाया/संक्षेपित किया जाना चाहिए। अगोपनीय सारांश में दिया गया ब्यौरा पर्याप्त होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय-वस्तु आसानी से समझी जा सके। तथापि अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना संक्षेपण योग्य नहीं है और संक्षेपण संभव क्यों नहीं है, इसके कारणों का ब्यौरा निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

प्रस्तुत की गई सूचना की जांच के उपरांत प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध का स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता हेतु अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्य अथवा सारांश रूप इसके प्रकटीकरण को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं।

सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में दिए गए कारण के ब्यौरे के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को निर्दिष्ट प्राधिकारी रिकार्ड में नहीं लेंगे। निर्दिष्ट प्राधिकारी, प्रदत्त कराने वाले पक्षकार द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किए बिना किसी भी पक्षकार के समक्ष इस प्रकट नहीं करेंगे।

10 सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

11. असहयोग

यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th February, 2011

(Sunset Review)

Subject : Sunset Review of anti-dumping duty imposed concerning imports of Viscose Filament Yarn originating in or exported from China PR.

No. 15/23/2010-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules), the definitive anti-dumping duty was originally imposed vide notification No. 14/23/2004-DGAD dated 4th April 2006 on imports of Viscose Filament Yarn (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country); whereupon the Anti-dumping duty was imposed vide Customs Notification No.45/2006 dated 24th May 2006. And whereas these findings were modified in a mid-term review investigation vide final findings No.15/8/2007-DGAD dated 22nd May 2009; whereupon the Anti-dumping duty was modified vide Customs Notification No.81/2009 dated 13th July 2009.

2. Product under consideration

The product involved in the original investigation was considered as Viscose Rayon Filament Yarn up to 150 deniers (and ± 4% permissible variation thereof) including mono filament yarn of less than 67 decitex also known as viscose filament yarn or VFY, Rayon Filament Yarn, Art Silk Yarn, Cellulose Yarn or Rayon Yarn and includes all yarns made of 100% viscose yarns such as dyed yarn, flat yarn, microfilament microyarn, twisted yarn (with the exclusion of embroidered yarn), doubled/ multiple ply yarn etc of VFY unless specifically excluded in this paragraph (also referred to as subject goods herein after) originating in or exported from China PR. However, the subject goods do not include sewing thread, fur yarn, fire retardant yarn, engineered yarn, embroidered yarn and air texturised yarn. The product under consideration for the purposes of this review remains the same as was in the original investigation.

The subject goods are classified under Customs sub-heads 54033100, 54033200, 54033300, 54034110, 54034120, 54034130, 54034140, 54034150, 54034160, 54034170, 54034180, and 54034190 though they have been reported to have been imported (in the investigations previously held on the subject) under other chapter heads as well (like chapter 55). Thus, Customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of these investigations.

3. Initiation:

In view of the order of the Hon'ble Delhi High court in the matter of *Indian Metal and Ferro Alloys Ltd V/s Designated Authority*, Writ Petition (Civil) No. 16393 of 2006 and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the AD Rules, the Authority hereby initiates a

735 GI/II-2

sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods and to examine whether the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. Countries/territory involved:

The country involved in this investigation is China PR.

5. Period of Investigation:

The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is 1st October 2009 to 30th September 2010 (12 months). However, injury analysis shall cover the years 2007-08, 2008-09, 2009-10 & POI. The data beyond POI may also be examined to determine likelihood of dumping and injury.

6. Procedure:

Having decided to review the final findings issued vide Notification No. 14/23/2004-DGAD dated 4th April 2006 that was modified in the mid-term review investigation vide final findings No.15/8/2007-DGAD dated 22nd May 2009 whereupon the Anti-dumping duty was imposed vide Customs Notification No.45/2006 dated 24th May 2006 and Customs Notification No.81/2009 13th July 2009 respectively; the Authority hereby initiates investigation to review the need for continued imposition of the duties in force and to examine whether cessation of the anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of ‘Dumping’ and ‘injury’ on imports of the subject goods originating in or exported from the subject country in accordance with the Act and the AD Rules. The review covers all aspects of Notification No. 14/23/2004-DGAD dated 4th April 2006 (final findings of the original investigation) that was modified in the mid-term review investigation vide final findings No.15/8/2007-DGAD dated 22nd May 2009.

7. Submission of Information:

The known exporters in subject country, the government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry, are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Department of Commerce
Room No.240, Udyog Bhawan,
New Delhi-110107.**

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

8. Time Limit:

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from

the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the ‘facts available’ on record in accordance with the AD Rules.

The domestic producers of the subject goods are being issued a questionnaire to respond within 40 days substantiating the need for continued imposition of the AD measures.

All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter within 40 days from the date of initiation of this investigation. All such interested parties, that intimate so, would be requested to offer their comments to the domestic producers’ response(s) within 40 days from the date of issuance of the letter to them regarding the need to continue or otherwise the AD measures.

9. Submission of information on confidential basis.

In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire’s response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either “confidential” or “non-confidential” at the top of each page.

Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary, a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Designated Authority.

The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Designated Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Designated Authority. The Designated Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

10. Inspection of public file:

In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

11. Non-cooperation

In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority